कृषि विभाग

दिनांक 1 जनवरी, 2008

संख्या 3225-कृषि-II(1)-2007/79.—हरियाणा के राज्यपाल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की गतिविधियों को संचालित करने के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित करके राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की कार्यकारिणी का गठन करते हैं :—

1.	मुख्य सचिव, हरियाणा	अध्यक्ष
2.	उपकुलपति, चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	सदस्य
3.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
4.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, योजना विभाग	सदस्य
5.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग	सदस्य
7.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग	सदस्य
8.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग	सदस्य
9.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, मत्स्य विभाग	सदस्य
10.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
11.	आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग	सदस्य
12.	उद्यान निदेशक, हरियाणा, पंचकूला	सदस्य
13.	निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विकास, हरियाणा, पंचकूला	सदस्य
14.	निदेशक, मत्स्य, हरियाणा, पंचकूला	सदस्य
15.	कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार का एक मनोनीत सदस्य (संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं), नई दिल्ली	सदस्य
16.	योजना विभाग, भारत सरकार का एक मनोनीत सदस्य, नई दिल्ली	सदस्य
17.	कृषि निदेशक, हरियाणा, पंचकूला	सदस्य-सचिव

राज्य स्तरीय मंजूरी समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

1. आर०के०वी०वाई० की श्रृंखला-1 के अन्तर्गत परियोजनाओं की मंजूरी।
2. स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की निगरानी।
3. योजनाओं के उद्देश्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किये जा रहे हैं।
4. यह सुनिश्चित करना कि प्रयासों और संसाधनों का दोबारा प्रयोग न करना पड़े।
5. परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए क्षेत्रगत अध्ययन करवाना/करना।
6. अपेक्षा के अनुसार समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन की शुरुआत करना।
7. राज्य कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के महत्व की किसी अन्य परियोजना का उत्तरदायित्व लेना।
8. यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्तर जिला विसंगतियां न हों।

राज कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 1st January, 2008

No. 3225-Agri. II(1)-2007/79.—The Governor of Haryana is pleased to constitute a State Level Sanctioning Committee (SLSC) for implementation of National Agriculture Development Programme (NADP)/Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) with the following composition :—

1.	Chief Secretary, Haryana	Chairman
2.	Vice Chancellor, CCS Haryana Agricultural University, Hisar	Member
3.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department	Member
4.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Rural Development Department	Member
5.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Irrigation Department	Member
6.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Forest Department	Member
7.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department	Member
8.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Planning Department	Member
9.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Fisheries Department	Member
10.	Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Environment Department	Member
11.	Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Animal Husbandry and Dairy Development Department	Member
12.	Director of Horticulture, Haryana	Member
13.	Director, Animal Husbandry and Dairy Development	Member
14.	Director, Fisheries, Haryana	Member
15.	Representative of Department of Agriculture and Cooperation, Government of India (not below the rank of Joint Secretary), New Delhi	Member
16.	Representative of Planning Commission, New Delhi	Member
17.	Director of Agriculture, Haryana	Member-Secretary

The State Level Sanctioning Committee shall perform the following functions :—

1. Sanctioning of the projects under Stream-1 of the RKVY.
2. Monitoring the progress of the sanctioned projects/schemes.
3. Reviewing the implementation of the schemes' objectives and to ensure that the programmes are implemented in accordance with the guidelines laid down.
4. Ensuring that no duplication of efforts or resources takes place.
5. Commissioning/Undertaking field studies to monitor the implementation of the projects.
6. Initiating evaluation studies from time to time, as may be required.
7. Undertaking any other project of importance to the State's Agriculture and allied sectors.
8. Ensuring that there are no inter-district disparities with respect to the financial patterns/subsidy assistance in the projects.

RAJ KUMAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Agriculture Department.